on the other hand attract basic plus auxiliary customs duty at 80 per cent. Thus, at present, generally the rate of import duty on raw materials for the electronic industry (including T.Vs) is lower than the rate of duty on the components. For imports under special schemes, such as, advance licensing scheme or imports by 100 per cent Export Oriented Units or units in Free Trade Zone/Export Processing Zone, import of raw materials is permitted duty free for use in the manufacture of products for export. The Government have no specific information about the import duty regime operating in respect of raw matedials in other TV manufacturing countries.

अतिरिक्त शेयर बाजारों के संबंध में फेरवानी समिति की सिफारिशें

2827. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेरवानी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी की अतिरिक्त शेयर बाजार स्थापित किए जाने चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं ; और

(ग) फेरवानी समिति की अन्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) श्री एम० जे० फेरवानी की अध्यक्षता में नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना हेतु नीति का सुझाव देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1991 में गठित एक अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि सरकार नई बम्बई, नागपुर, ग्वालियर, चंडीगढ़ और शिमला में पांच अतिरिक्त स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करें। सिद्धान्त रूप में सरकार नई बम्बई में एक राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज की स्थापना के लिए अगस्त, 1991 में पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी है । अन्य चार प्रस्तावित एक्सचेंजों की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मुख्य जिम्मेदारी प्रवर्तकों की है ।

(ग) अन्य मुख्य सिफारिशें राष्ट्रीय निपटान और समझौता पद्धति, एक केन्द्रीय निक्षेपी न्यास और एक प्रतिभूति सुविधा समर्थन निगम की स्थापनाओं से संबंधित है ।

Nadkarni Committee's Report on securities trading

2828. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India might be forced to reintroduce the system of ready forward trading in securities by banks, albeit in a modified form, in the coming days as reported in the Financial Express of the 8th July, 1992, if so, the details thereof;

(b) by when the Nadkarni Committee Report in this regard is expected to be received by Government and whether before reintroducing/revamping this system Government propose to consult securities trading officials, of various banks, financial services, companies, chiefs of Public Sector Banks, etc.;

(c) whether Government also propose to have a fresh look over the system of appointment of brokers and commission paid to them;

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor; and

(e) in what manner the activities of unscrupulous brokers is proposed to be checked?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Reserve Bank of India (RBI) has informed that they have no proposal at present to reintroduce ready forward deals in securities.

(b) The Nadkarni Committee which has been set up by RBI is expected to submit

its Report within the next few weeks. It is premature to indicate whether consultation of the type referred to in the question is necessary.

(c) to (e) Reserve Bank of India has not made any proposal in this regard. It is the RBI which maintains a panel of brokers approved by it for dealings with it in Government securities. If any adverse activities of any broker comes to the notice of the RBI, the names of the broker is de-listed by the RBI due after consideration.

भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में लिपिकों और टंककों के रिक्त पद

2829. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की नई दिल्ली शाखा में मार्च, 1988 से 30 जून, 1992 तक कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, कार्यभार के बढ़ जाने और अन्य कारणों से लिपिकों, नोट/सिक्का परीक्षकों, अंग्रेजी टंककों और हिन्दी टंककों के प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की नई दिल्ली शाखा में जून 1992 से पहले नियुक्त ऐसे कितने टंकक हैं जो हर दृष्टि से लिपिक और नोट/सिक्का परीक्षक, के पदों पर परिवर्तन की पात्रता प्राप्त कर चुके हैं किन्तु जिन्हें अभी तक लिपिक अथवा नोट/सिक्का परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ग) उपरोक्त श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या इस अवधि के दौरान इन श्रेणियों के पदों पर कोई नियुक्तियां कर ली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार सूचना दी है :-

(क) और ( ) मार्च, 1988 से जून 1992 तक की अवधि के दौरान लिपिक ग्रेड II/सिक्का-नोट परीक्षक ग्रेड II के 205 पद और टाइपिस्टों के 12 पद भर लिए गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्तियों और अन्य कारणों से होने वाली रिक्तियां भी शामिल हैं ;

(ख) ऐसे सात पात्र टाइपिस्ट हैं, जो लिपिक ग्रेड II/सिक्का-नोट परीक्षक ग्रेड-II के संवर्ग में स्विच ओवर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ग) बैंक के केंद्रीय कार्यालय में स्टाफ की आवश्यकताओं के बारे में आवधिक समीक्षा की जाती है और बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में काम के कुल भार को ध्यान में रखने के बाद वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों के भरने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

Restructuring of NRI Deposit Schemes

2830. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NRI deposit schemes are being restructured; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Madam.

(b) Does not arise.

Arrest of a Finance Ministry Officer by CBI

2831. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether an official of his Ministry has ben arrested by CBI for allegedly leaking some valuable information regarding the Asea Brown Bovery Electric Locomotive deal;